जयराम रमेश
JAIRAM RAMESH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT,
DRINKING WATER AND SANITATION
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

दिनांक 18 जून, 2012

288

प्रिय अर्जुन मुण्डाजी,

मुझे सारन्दा विकास योजना के कार्यान्वयन के बारे में कुछ चिन्ताजनक जानकारियां मिली हैं, जिनके बारे में मैने सोचा कि आपको अवगत करा दूं :–

- सड़क निर्माण का कार्य धीमा चल रहा है और जो सड़कें शुरू की गई हैं उनमें से केवल एक सड़क का कार्य प्रगति पर है;
- हैंडपम्प लगाने का कार्य शुरू हो चुका है जबकि यह कार्य बाहरी गांवों में और सड़कों के किनारे किया जा रहा है। भीतरी गांवों को अभी कवर किया जाना है;
- इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 6000 मकानों को स्वीकृति तो दी जा चुकी है, जबकि कार्य आदेश जारी करने का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यहां तक कि जिन मामलों में चैक जारी कर दिए गए हैं उन मामलों में भी निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किये गए हैं;
- भीतरी गांवों की पाठशालाओं में अधिकतर अध्यापक आते ही नहीं हैं। अनेक पाठशालाओं में बच्चों को मध्याह्न भोजन (मिड डे मील) नहीं दिया जा रहा है। अध्यापक मुख्यतः गैर आदिवासी हैं और स्थानीय भाषा में बच्चों के साथ बातचीत करने में सक्षम नहीं हैं;
- बड़ी संख्या में पात्र परिवारों को बीपीएल सूची में शामिल न किए जाने के मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं हुई है, यद्यपि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 28 मार्च, 2012 को एक पत्र भी जारी कर दिया था।

मुझे यह भी बताया गया है कि चाईबासा के जिला कलक्टर को सरायकेला का भी अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह पूरी तरह से राज्य सरकार का निर्णय है। आपके अधिकारों में हस्तक्षेप करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तथापि, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही जिलों में काम का बोझ बहुत अधिक है और इसमें बड़ी जिम्मेवारियां शामिल हैं।

मुझे यह भी उम्मीद है कि सारन्दा विकास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति हेतु अधिसूचना को अन्ततः जारी कर दिया गया होगा। पिछली बार जब मैंने इसकी जॉच की, यह अधिसूचना जारी नहीं की गई थी। आपसे बेहतर इस बात को कौन समझ सकता है कि बिना किसी सरकारी आदेश के एक अधिकारी, आपके द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने में असहाय होगा।

सादर,

आपका,

जयराम रमेश

(जयराम रमेश)

श्री अर्जुन मुण्डा,
मुख्य मंत्री,
झारखण्ड सरकार,
रॉची।

PS: आशा है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे।

जयराम रमेश
JAIRAM RAMESH

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्री
भारत सरकार
कृषि भवन, नई दिल्ली-110114
MINISTER OF RURAL DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
KRISHI BHAVAN, NEW DELHI-110 114

87

My dear Arjun Mundaji –

24th December 2011

I would like to thank you for the function organised in Chota Nagara Panchayat in Saranda area on December 2nd 2011. There has been a good feedback from various quarters on the Saranda initiatives. The Adviser to Hon'ble Prime Minister Sri T.K.A Nair recently visited West Singhbhum district and he was also appreciative of the developmental initiatives in the area. I am also happy to inform you that my ministry has already sanctioned 6000 IAY houses for the six Panchayats in the Saranda core area. Further, the six watershed development proposals for West Singhbhum have also been cleared.

As you know, I had meetings with the officers and also public representatives in Chaibasa during my visit. I want to bring to your notice some of the suggestions/issues which came up during my interactions with various stakeholders:-

1. Apart from the core area, some of the Gram Panchayats in the fringe area of the Saranda should also be included in the plan. There can be a separate agency, **"Saranda Development Authority"** which can implement the developmental plans in an integrated manner with a clear mandate.
2. This authority can be headed by the Nodal officer, assisted by a young IAS officer. All the departments working in the area should report to this authority so that there is a single focussed approach for development of Saranda region.
3. The District level and the State level monitoring committee (including representatives from Police and Central Para military forces) can regularly meet and monitor and coordinate the activities of this authority. A realistic time frame is also required for achieving the various developmental goals.
4. The Forest department will have to restart the activities in the Saranda area. I am told that there are vacancies in the forest guards in the Division. One suggestion which came up was to recruit the local educated tribal youth to fill up these posts. This will go a long way in ensuring a stake of the local tribals in the Forest Department activities.

014

5. The issue of allotting the land for the security camps has been coming up in every meeting. The DG CRPF has informed that the CRPF companies have already reached Jharkhand and are waiting for the allotment of nearly 24 camps to position the security forces. Once these forces are in place, then security situation in the interiors of Saranda will improve further.

I request your personal intervention on the above suggestions to take forward the development plans for Saranda.

With regards,

Yours sincerely,

(Jairam Ramesh)

Shri Arjun Munda
Chief Minister
Government of Jharkhand